विकास केन्द्रों के स्थापना स्थलों का पहले ही पता लगा लिया गया है और इनकी घोषणा कर दी गई हैं। शेष विकास केन्द्रों के स्थापना स्थलों के लिए प्रस्ताव जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । इस योजना को 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ।

पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना

308. **श्री रणजीत सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु वहां औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने औद्योगिक विकास केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव था और इस योजना के अधीन कुल कितने धन के व्यय का अनुमान है ;

(ग) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वियन हेतु आवश्यक धन का प्रावधान किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितना धन खर्च करने का प्रस्ताव है और तदनुसार अब तक कुल कितने केन्द्रों की स्थापना की गई थी ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (घ) सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये देशभर में 100 विकास केन्द्र स्थापित करने की एक योजना जून, 1988 में घोषित की थी। पहले चरण में 70 विकास केन्द्र विकसित करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 61 विकास केन्द्रों के स्थापना स्थल का पता लगा लिया गया है और इनकी घोषणा कर दी गयी है । केन्द्र सरकार ने विकास केन्द्रों के लिये परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिये राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं । राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से प्राप्त परियोजना रिपोर्टों का केन्द्र सरकार द्वारा विधिवत मूल्यांकन व अनुमोदन किया जायेगा, जिसके बाद निधियां जारी की जायेंगी ।

प्रत्येक विकास केन्द्र को लगभग 25–30 करोड़ रु० की लागत से विकसित किया जायेगा । चालू वित्तीय वर्ष 1990-91 में इस योजना के लिए 30 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है । इस योजना का कार्यान्वयन 8वीं योजना अवधि के दौरान आरम्भ करने का प्रस्ताव है ।

विनिर्माताओं द्वारा साइकिलों की कीमतों में वृद्धि

309. **श्री रणजीत सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1991 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "पैट्रोल प्राइस हाइक ए बून फार बाइसिकिल कंपनीज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि साइकिल विनिर्माताओं ने अपने उत्पादों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने साइकिलों की कीमतों में हुई इस अवांछनीय वृद्धि को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) जी, हां ।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार, जुलाई, 1990 से जनवरी 1991 तक की अवधि में साइकिलों के कारखाना बाह्य मूल्य में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।